प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक २१ मार्च, 2017**

विषय- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान के अन्तर्गत जनपद-गाजियाबाद के वि०ख०-रजापुर एवं भोजपुर में कौशल विकास योजना हेतु केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(6)/2012-पी0पी0, दिनांक 30.09.2013 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-जी०आई०-03/52-1-14-1(126)/13, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे उक्त जनपद में कौशल विकास योजना हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** जिलाधिकारी के पक्ष में अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(6)/2012-पी0पी0, दिनांक 28.02.2017 से उक्त कौशल विकास योजना हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 91.00 लाख के सापेक्ष अवशेष **द्वितीय किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 45.50 लाख (रूपये पैतालिस लाख पचास हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 200.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(के0-100/रा0-00)										**(रू0 लाख में)**
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्त **द्वितीय किश्त**		अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	**गाजियाबाद**	वि०ख०-रजापुर में अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजना	150	0.14	21.00	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50
	तदैव	वि०ख०-भोजपुर में अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास योजना	500	0.14	70.00	0.00	35.50	35.00	0.00	35.00
		योग								**45.50**

http://sirsaapdesh.up.nic.in

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कौशल विकास योजना की कार्यवाही जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित जिला शिक्षा समिति के सामान्य पर्यवेक्षण में की जायेगी। सम्बन्धित शिक्षाधिकारी उक्त कौशल विकास योजना हेतु समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे।

3- कार्य को अनुमोदित लागत से ही 04 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी।

4- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा।

6- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

7- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8- प्रश्नगत कौशल विकास योजना के सम्बन्ध में व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। विद्वालयों के भवन की डिजाइन एवं क्षेत्रफल वही होगा जो केन्द्र/राज्य सरकार के व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

9- जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर कौशल विकास योजना की गुणवत्ता की समीक्षा की जायेगी, ताकि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा ।

11- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा शिक्षण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

13- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये शिक्षण कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान का कार्यान्वयन (के0 100/रा0 00-के0+रा0)-20-सहायता अनुदान –सामान्य (गैर वेतन)** के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2015-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

UniCode Gov. Inter College. G.O

संख्या-जी0आई0-16(1)/बावन-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत कौशल विकास योजना हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कौशल विकास योजना के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से अनुदान न प्राप्त किया गया हो।

7- निजी सचिव, मा0मंत्री,अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

8- निजी सचिव, सचिव/प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव/प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- जिलाधिकारी/जिला व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

12- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीना नाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in